

Q. 6 अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से आप क्या समझते हैं?

What do you mean by International Environment?

Ans. आधुनिक युग में प्रत्येक व्यवसायिक संस्थान देश की अर्थ-व्यवस्था के साथ-साथ अप्रत्याक्ष रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आर्थिक-सांख्यिक परिवर्तनों से व्यवसाय की प्रभावित होना है। अतः संस्था के क्रियाविलेय तथा लाभदायकता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली उन व्यापक घटनाओं का विश्लेषण किया जाए।

Q. 7 वैधानिक वातावरण से आप क्या समझते हैं?

What do you mean by Legal Environment?

Ans. व्यवसाय तथा कानून में परस्पर अनिवार्य संबंध है। प्रबंधकों को हमेशा कानून के दायरे में ही काम करना पड़ता है। प्रत्येक संस्था कानून के विद्यालय जाल से घिरा हुआ है। वैधानिक वातावरण जहाँ एक ओर अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर यह अनेक प्रतिबंध तथा बाधाएँ भी उत्पन्न करता है।

वैधानिक वातावरण के अन्तर्गत विभिन्न कानूनी नीतियाँ, विभिन्न वैधानिक नियंत्रण, काम-संबंधी कानून, (Labour Law), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), व्यावसायिक कानून (Business Law), औद्योगिक अधिनियम, राजभाषिक कानून, आदि आते हैं। जहाँ -

1. कंपनी अधिनियम - Company Act
2. अनुबंध अधिनियम - Contract Act
3. बस्तु-विक्रय अधिनियम - Sale of Goods Act
4. कारखाना अधिनियम - Factory Act
5. औद्योगिक विवाद अधिनियम - Industrial Dispute Act
6. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम - Minimum Wages Act
7. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम - Workmen Compensation Act
8. आयात-निर्यात नियंत्रण अधिनियम
Import and Export Control Act
9. विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम (FERA)
Foreign Exchange Regulation Act
10. सार्वजनिक वितरण नीति -
Public Distribution Policy
11. लाइसेंसिंग नीति - Licensing Policy
12. साझेदारी अधिनियम - Partnership Act
13. पूँजी नियंत्रण अधिनियम

Control of Capital Issue Act,

आवश्यक कानूनी अनुभवियाँ

आदि वैधानिक वातावरण के तब तक नहीं जा सकते हैं। इन सबकी आवश्यकतानुसार प्रशासकों को जान करी होनी चाहिए। सरकार के तीनों अंग अर्थात् विधायिका (Legislature), प्रशासकीय (Executive), तथा न्यायपालिका

(9)

(10)

Date			
Page No.			

(Judiciary) व्यवसाय तथा उनके प्रबंध को प्रभावित किए बिना नहीं रहते। विधायिका किली कार्यवाही का निर्धारण करती है। सरकार विधायिका द्वारा बनाई गई कार्यवाही को लागू करती है तथा नगरपालिका विधायिका तथा प्रशासकीय दोनों के कार्यों को देखती है कि उनके द्वारा किए गए कार्य जनहित में हैं तथा संचालित होने के उचित और किफायती हैं।